R.N.I. No.: 23316/72

बाबर ने कहा था कि हिन्दू गुणवान होते हैं किन्तु ईर्ष्यालु होते हैं, वे एक दूसरे को नीचा दिखाने में शक्ति नष्ट करते रहते हैं। क्या यह आज भी सत्य नहीं है?

—बाबा फरलिया

चार सच्चे साथी

1. ईश्वर 2. शरीर
3. बुद्धि 4. पुरुषार्थ

केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा विज्ञापनों के लिए स्वीकृत

हिन्दी साप्ताहिक राष्ट्र चेतना का सजग प्रहरी

शत्रुघ्न

जाके सुमिरन ते रिपु नाशा । नाम 'शत्रुघ्न' वेद प्रकाशा ।।

DAVP Code: 120646

भ्रष्टाचार से लड़िए, डरिए मत, हरिद्वार से प्रकाशित साप्ताहिक शत्रुघ्न को भ्रष्टाचार के मामले में फोन, ईमेल करें या लिखें।

-:सम्पादकीय कार्यालयः-

बी—72 न्यू विष्णु गार्डन
पो. गुरूकुल कांगड़ी, हरिद्वार
मो. 9319034059,9219669691
Email:bkshastri02@gmail.com

शुभाशीर्वादः संस्थापक सम्पादक स्व0 रामस्वरूप फरलिया स्वतंत्रता सेनानी

वर्ष—53 अंक—52 हरिद्वार शुक्रवार, 2 मई 2025 पृष्ठ—4 एक प्रति—एक रुपया

चारधाम यात्रा के दृष्टिगत सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाय: मुख्यमंत्री

सू.ए.लो.सं.वि.

देहरादून। राज्य के धार्मिक और पर्यटक स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी जाए। चारधाम यात्रा के दृष्टिगत भी सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाय। जिलाधिकारियों द्वारा अपने जनपदों में इसकी नियमित निगरानी की जाए। चारधाम यात्रा के दौरान और अन्य महत्वपूर्ण मामलों में विभिन्न माध्यमों से फेक न्यूज चलाने वालों पर तत्काल कार्रवाई की जाए और जिलाधिकारियों द्वारा सही जानकारी नियमित रूप से विभिन्न माध्यमों से साझा की जाए। ये निर्देश मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री आवास से वर्चुअल बैठक के दौरान जिलाधिकारियों को दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में किरायेदारों का सत्यापन न कराने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। ठेली, फड़ और झुग्गी झोपडियों में रहने वालों का भी सत्यापन किया जाए। राशन कार्ड, आधार कार्ड, बिजली के कनेक्शन आयुष्मान कार्ड और अन्य दस्तावेज अपात्र लोगों को देने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जाए। जनपदों में जिलाधिकारियों द्वारा सभी विभागों के

अधिकारियों की ड्यूटी सत्यापन के लिए लगाई जाए। वनाग्नि प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने के साथ ही वनाग्नि की घटनाओं में संलिप्त पाये जाने वालों पर कठोर कार्रवाई के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिये है। मुख्यमंत्री ने डेंगू पर प्रभावी नियंत्रण के लिए भी सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि नियमित फॉगिंग के साथ ही डेंगू से बचाव के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाए। अस्पतालों में बिजली की रोस्टिंग न करने और ग्रीष्म काल में प्रदेश में बिजली और पानी की सुचारू आपूर्ति रखने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिये हैं। प्रदेश में पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी कैंचीधाम वार्षिकोत्सव के दृष्टिगत भी सड़कों की बेहतर स्थिति के साथ पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। सभी जिलाधिकारियों को मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये हैं कि वे समयसमय पर विभिन्न कार्यालयों का औचक निरीक्षण करें। जिससे व्यवस्थाएं भी सही बनी रहेंगी और जन समस्याओं का समाधान भी तेजी से होगा। उन्होंने कहा कि बहुद्देशीय शिविरों, तहसील दिवस और बीडीसी की बैठकें नियमित की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्मार्ट मीटर की प्रगति की नियमित निगरानी की जाए। विद्युत बिल की शिकायतों को गंभीरता से लिया जाए। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर तत्काल कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि 10 करोड़ तक के टेंडर स्थानीय ठेकेदारों को ही मिले। इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के साथ भी जिलाधिकारी नियमित संवाद बनाये रखें।

मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना को बढ़ावा देने के लिए सभी जनपदों को टारगेट देकर लक्ष्य पूर्ण करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिये हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा के दृष्टिगत यातायात प्रबंधन और सड़कों की स्थिति सही रहे इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। चारधाम यात्रा के लिए घोड़ाखच्चर के स्थानीय संचालकों को प्राथमिकता दी जाए। चारधाम यात्रा मार्ग में श्रद्धालुओं के लिए सभी मूलभूत सुविधाओं के साथ स्वच्छता और सौन्दर्यीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाए। यात्रा मार्गों पर रेट लिस्ट चेक कर ली जाए यह सुनिश्चित किया जाए कि ओवर रेटिंग की शिकायत न आये। बैठक में प्रमुख सचिव आर.के सुधांशु, आर. मीनाक्षी सुंदरम, अपर पुलिस महानिदेशक ए.पी. अंशुमन, गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पाण्डेय, वर्चुअल माध्यम से कुमांऊ कमिश्नर दीपक रावत एवं सभी जिलाधिकारी उपस्थित थे।

अपात्रों को लाभ देने वालों के विरूद्ध होगी कार्यवाही: डीएम

शत्रुघ्न संवाददाता

हरिद्वार। जिलाधिकारी कर्मेन्द्र सिंह ने अवगत कराया कि विभिन्न स्रोतो से संज्ञान में आया है कि जनपद हरिद्वार में बाहरी राज्यों के व्यक्तियों द्वारा अवैध रुप से निवास किया जा रहा है। ऐसे व्यक्ति जनपद में विशेष तौर पर किराये के मकान में तथा झुग्गी झोपड़ियों में निवास कर रहे है. एवं ठेली, फड एवं अन्य व्यवसाय में सम्मिलित है। ऐसे व्यक्तियों के द्वारा अनाधिकृत रुप से राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड निवार्चन प्रमाण पत्र, प्रधानमंत्री आवास योजना, सामान्य निवास प्रमाण—पत्र और अन्य जरुरी दस्तावेज प्राप्त कर लिये गये है, जिसके कारण उन्हे राज्य की विभिन्न जन—कल्याणकारी योजनाओं का अपात्र होते हुए भी अनुचित लाभ प्राप्त हो रहे है साथ ही राज्य के संशाधनों पर भी अनुचित दबाव पड़ रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि इसके अतिरिक्त बाहरी राज्यों के व्यक्तियों ने नगरीय/ग्रामीण क्षेत्रों के सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध रूप से निवास करने से तथा इनकी संदिग्धता के दृष्टिगत शान्ति एवं कानून व्यवस्था प्रभावित होने की संभावना बन सकती

है। ऐसी दशा में अपात्रों द्वारा जन—कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाये जाने तथा सुरक्षा के दृष्टिगत भी इनका सत्यापन कराया जाना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि सत्यापन के उपरान्त ऐंसे व्यक्तियों के विरुद्ध एवं इन व्यक्तियों को अनुचित लाभ पहुँचाने वाले कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि सत्यापन अभियान हेतु तीन समितियों का गठन किया गया है। उन्होंने समितियो के गठन के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों हेतु गठित समिति में उपजिलाधिकारी— अध्यक्ष, पुलिस क्षेत्राधिकारी—सदस्य, खण्ड विकास अधिकारी—सदस्य, क्षेत्रीय खाद्य निरीक्षक—सदस्य, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक—सदस्य, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत)—सदस्य, विकास प्राधिकरण के सक्षम अधिकारी— सदस्य नामित किए गये है। इसी क्रम में नगरीय क्षेत्र हेतु गठित समिति में (नगर निगम) नगर आयुक्त—अध्यक्ष, उपजिलाधिकारी—सदस्य/सचिव, पुलिस क्षेत्राधिकारी—सदस्य, सहायक नगर आयुक्त—सदस्य, क्षेत्रीय खाद्य निरीक्षक—सदस्य, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक—सदस्य, विकास प्राधिकरण के सक्षम अधिकारी—सदस्य नामित किये गये है तथा नगरीय क्षेत्रों (नगर पालिका/नगर पंचायत) के लिए उपजिलाधिकारी—अध्यक्ष, पुलिस क्षेत्राधिकारी—सदस्य, अधिशासी अधिकारी—सदस्य/सचिव, क्षेत्रीय खाद्य निरीक्षक—सदस्य, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक—सदस्य, विकास प्राधिकरण के सक्षम अधिकारी—सदस्य नामित किये गये हैं। उन्होंने सभी गठित समितियों के अध्यक्षों को स्पष्ट आदेश जारी किये हैं कि सत्यापन अभियान विस्तृत रूप से किया जाना है। इसलिए अध्यक्ष अपने क्षेत्रान्तर्गत उपसमिति का गठन अपने—अपने स्तर से तत्काल कर लें।

भाकियू क्रांति ने लगाया औद्योगिक इकाईयां में मजदूरों और कर्मचारियों के शोषण का आरोप

शत्रुघ्न संवाददाता

हरिद्वार। भारतीय किसान यूनियन क्रांति ने जनपद हरिद्वार में स्थापित औद्योगिक इकाईयों में मजदूरों और कर्मचारियों के शोषण किए जाने का आरोप लगाते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। प्रैस क्लब में पत्रकारों से वार्ता करते हुए भाकियू क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सैनी ने आरोप लगाया कि जनपद में स्थापित औद्योगिक इकाईयों में कर्मचारियों और मजूदरों का शोषण किया जा रहा है।

वेतन बढ़ाने और सुविधाओं की मांग करने पर कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया जाता है। शिकायत करने के बावजूद संबंधित अधिकारी कर्मचारियों को न्याय दिलाने में विफल साबित हो रहे हैं। सरकार भी इस और कोई ध्यान नहीं दे रही है। विकास सैनी ने कहा कि जेके टायर कंपनी के हजारों कर्मचारी शोषण और उत्पीड़न के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कर्मचारियों के समर्थन में भाकियू क्रांति व्यापक स्तर पर धरना प्रदर्शन करेगी। इसके बाद भी कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो जिलाधिकारी का घेराव किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि सरकार की किसानों को लेकर नीयत साफ नहीं है। एक तरफ केंद्र सरकार किसानों की आय दोगुना करने की बात करती है। दूसरी और उत्तराखंड सरकार किसानों के बकाया 215 करोड़ रूपए नहीं दे पा रही है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार श्रम कानूनों का पालन सुनिश्चित करे और किसानों, मजदूरों के उत्पीड़न पर रोक लगाए। यदि सरकार मजदूरों और किसानों को न्याय नहीं दिला पायी तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। पत्रकारवार्ता के दौरान राष्ट्रीय प्रवक्ता तौफीक अहमद, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनोद प्रजापति, राष्ट्रीय सलाहकार पदम सिंह, जिलाध्यक्ष अजीम कुरैशी, जिला महासचिव सूरज राजपूत भी मौजूद रहे।

सम्पादकीय

जंग में भारत के साथ कौन से देश आएंगे

अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, इजरायल, जापान, रूस, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भारत का खुलकर साथ देंगे। जबकि मौजूदा हालात को देखें तो आतंकी संगठन हमास, लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे उसके पाले पोसे आतंकी संगठन ही साथ खड़े नजर आ रहे हैं। कई इस्लामिक मुल्क भी पाकिस्तान से किनारा करते नजर आ रहे हैं। सऊदी अरब तो पहले कह चुका है कि निर्दोष लोगों पर आतंकी हमला बर्दाश्त नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ अच्छे रिश्तों की वजह से कतर और यूएई जैसे देश भी पाकिस्तान का साथ नहीं देंगे। यानी पाकिस्तान पूरी दुनिया में इस वक्त अलग थलग दिखाई पड़ रहा है। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि जब फंस जाओ परेशान हो जाओ तो मदद की भीख मांगना शुरू कर दो। फोन की घंटियां बजनी शुरू हो चुकी हैं। पिछले दो–तीन दिनों में वहां के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ने चीन, ईरान और ब्रिटेन में अपने समकक्षों से बात की। ये तीन तो ऐसे हैं जिनकी जानकारी सामने आ गई। बाकी किनसे और कैसी बात हुई इसकी लिस्ट कई गुणा लंबी हो सकती है। ये सवाल छिड़ी है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जंग हुई तो कौन से देश हमारे साथ आएंगे, कौन पाकिस्तान का पक्षधर होगा। कौन से देश टांग अड़ाने से कतराएंगे और कौन से देश थाली के बैंगन के समान होंगे।

हमारी सरकार युवाओं में टेक्नोलॉजी के प्रति रुचि पैदा करने का प्रयास कर रही है: सीएम

सूएलोसंवि

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून छावनी के जसवंत ग्राउंड में आयोजित ''सूर्या ड्रोन टेक 2025'' कार्यक्रम में ड्रोन प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड को डिफेंस प्रोडक्शन हब के रूप में स्थापित करने का संकल्प व्यक्त करते हुए कहा कि हमारी सरकार युवाओं में टेक्नोलॉजी के प्रति रुचि पैदा करने का प्रयास कर रही है।

भारतीय सेना की सेंट्रल कमांड द्वारा सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स (एस.आई.डी.एम.) के सहयोग से आयोजित यह दो दिवसीय प्रदर्शनी (29–30 अप्रैल, 2025) देश में विकसित अत्याधुनिक ड्रोन प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित कर रही है। जो बहुआयामी सैन्य आवश्यकताओं के अनुरूप है और ''आत्मनिर्भर भारत'' अभियान से प्रेरित है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड जैसे भौगोलिक दृष्टि से संवेदनशील राज्य मे ड्रोन तकनीक आपादा राहत कार्यों के लिए वरदान सिद्ध हो रही है। इसलिए हमारी सरकार का प्रयास है कि हमारे युवा न केवल ड्रोन विशेषज्ञ बनें, बल्कि नागरिक उपयोग के लिए भी टेक्नोलॉजी आधारित समाधान विकसित करें। हमारी सरकार युवाओं को इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ाकर उत्तराखण्ड को ड्रोन एवं रक्षा विनिर्माण के क्षेत्र में अग्रणी बनाने की दिशा में गंभीरता से कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी नई औद्योगिक नीतियों में रक्षा उत्पादन और टेक इनोवेशन को विशेष प्राथमिकता दी गई है। सूर्या ड्रोन टेक 2025 विज्ञान, प्रौद्योगिकी और प्रतिभा का समागम है। इस प्रकार के आयोजन न केवल आधुनिक तकनीकी उपलब्धियों के प्रदर्शन हेतु विशिष्ट मंच प्रदान करते हैं, बल्कि हमारे नौजवानों को ड्रोन और तकनीकी के क्षेत्र में इनोवेशन के लिए प्रेरित भी करते हैं। यह उत्तराखण्ड को ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में भी एक ठोस कदम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत में ड्रोन टेक्नोलॉजी और सैन्य क्षेत्र में नवाचार को निरंतर प्रोत्साहित किया जा रहा है। सैन्य क्षेत्र में नवाचार की महत्ता को समझते हुए हमारी सरकार भी उत्तराखण्ड में रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है।

इस दौरान कार्यक्रम में मध्य कमान और सोसायटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चर्स के सभी सदस्य, ड्रोन विशेषज्ञ, स्टार्टअप,MSME एनसीसी कैडेट्ड और स्कूली छात्र मौजूद रहे।

पहलगाम में हुआ आतंकी हमला भारत की एकता एवं अखंडता पर आघात है

शत्रुघ्न संवाददाता

कुरुक्षेत्र। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के पहलगाम में हुए भयावह आतंकवादी हमले में मारे गये निर्दोष लोगों को मातृभूमि सेवा मिशन द्वारा संचालित मातृभूमि शिक्षा मंदिर के बच्चों ने विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। बच्चों ने आतंकवादियों द्वारा निर्दयता पूर्वक मारे गये सभी लोगों के आत्मिक शांति के लिए परमपिता परमेश्वर से भारतमाता के चित्र के समक्ष प्रार्थना किया। मातृभूमि शिक्षा मंदिर के बच्चों ने पहलगाम में मारे गये सभी लोगों के परिवार जनों को दुःख की इस घड़ी में भगवान से यह अपार कष्ट सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना किया। सभी विद्यर्थियों ने पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए। मातृभूमि सेवा मिशन के संस्थापक डा. श्रीप्रकाश मिश्र ने पहलगाम में मारे गये सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम में हुआ भयावह आतंकवादी हमला न केवल भारत को बल्कि पूरे विश्व को झकझोर कर रख दिया है। हमले में 26 लोगों की मौत हो हुई है। इस कायराना हमले में 17 लोग घायल भी हुए हैं। इस हमले के शिकार हुए अधिकतर लोग पर्यटक थे, जो अपने परिवारों के साथ मिनी स्विट्जरलैंडश कहे जाने वाले बायसरन घूमने आए थे। 2019 में पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद सबसे बड़ा हमला है। अब भारत सरकार को पाकिस्तान के आतंकवादियों के इस कायराना पूर्ण हमले के खिलाफ कड़ी से कड़ी जबाबी कार्यवाही करनी चाहिए। जिससे भविष्य में पाकिस्तानी आंतकवादी संगठन भारत की ओर आँख उठाकर देख भी न सके। आजादी के बाद से पाकिस्तान की धरती से निरंतर भारत को असहज एवं कमजोर करने का प्रयास होता रहा है। यह हमारी सरकारों की कहीं न कहीं कमजोरी एवं कमी रही और कि आज तक एक देश में पाकिस्तान की आतंकवादी गतिविधियो को समाप्त नही कर सके। आज भारत अपनी सीमा सुरक्षा साहित विभिन्न संकटो का सामना कर रहा है, ऐसे में समस्त देशवासियो का कर्तव्य है देश की इस संकट की घड़ी में सारे मतभेद भुलाकर एकजुट होकर भारत को मजबूत करे।

डा. श्रीप्रकाश मिश्र ने कहा पहलगाम में हुआ कुर आतंकी हमला भारत की एकता एवं अखंडता पर आघात है। अब समय आ गया है भारत सरकार अपनी दृढ इच्छाशक्ति का परिचय देते हुए आतंकवाद एवं आतंवादियों का समूल नष्ट करके आजादी के बाद से अब तक आतंकवाद में मारे गये सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करे। मातृभूमि शिक्षा मंदिर जे विद्यार्थियों ने शांतिपाठ करके सभी मृतात्माओं को नमन किया।

भगवान परशुराम का सामाजिक दर्शन मुख्यत न्याय, धर्म, और समाज सुधार पर आधारित है: डॉ. श्रीप्रकाश मिश्र

शत्रुघ्न संवाददाता

कुरुक्षेत्र। भगवान परशुराम ने एकता का सूत्र संसार को दिया है। सभी जाति और समाजों में समरसता का संदेश दिया है। भारतीय वाङमय में सबसे दीर्घ जीवी चरित्र परशुराम जी का है। सतयुग के समापन से कलयुग के प्रारंभ तक उनका उल्लेख मिलता है। भगवान परशुराम जी के जन्म समय को सतयुग और त्रेता का संधिकाल माना जाता है। यह विचार भगवान परशुराम प्रकाट्योत्सव के उपलक्ष्य में मातृभूमि शिक्षा मंदिर द्वारा आयोजित लोक मंगल संवाद में कार्यक्रम में मातृभूमि सेवा मिशन के संस्थापक डा. श्रीप्रकाश मिश्र ने व्यक्त किये। कार्यक्रम का शुभारम्भ भगवान परशुराम के विग्रह के समक्ष पुष्पार्चन एवं दीप प्रज्ज्वलन से हुआ। मातृभूमि शिक्षा मंदिर के विद्यार्थियों ने भगवान परशुराम को नमन करते हुए उनके दिखाये मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। विद्यार्थियों ने भगवान परशुराम के जीवन से सम्बन्धित प्रेरक प्रसंग भी प्रस्तुत किये।

लोक मंगल संवाद कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए मातृभूमि सेवा मिशन के संस्थापक डा.श्रीप्रकाश मिश्र ने कहा भगवान परशुराम का सामाजिक दर्शन मुख्यत न्याय, धर्म, और समाज सुधार पर आधारित है। वे अन्याय के विरुद्ध थे और उन्होंने क्षत्रिय समाज के अहंकारी राजाओं को पराजित किया, जो समाज रक्षण का मूल धर्म भूल गए थे। साथ ही, उन्होंने सामाजिक समरसता और भूमि सुधार के लिए भी कार्य किया। भारतीय इतिहास में इतना दीर्घजीवी चरित्र किसी का नहीं है। वे हमेशा निर्णायक और नियामक शक्ति रहे। दुष्टों का दमन और सत–पुरूषों को संरक्षण उनके चरित्र की विशेषता है। उनका चरित्र अक्षय है, इसलिए उनकी जन्म तिथि वैशाख शुक्ल तृतीया को माना गया। इस दिन का प्रत्येक पल, प्रत्येक क्षण शुभ मुहूर्त माना जाता है। विवाह के लिए या अन्य किसी शुभ कार्य के लिए अक्षय तृतीया के दिन अलग से मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है। उनके जीवन का समूचा अभियान, संस्कार, संगठन, शक्ति और समरसता के लिए समर्पित रहा है। डा. श्रीप्रकाश मिश्र ने कहा भगवान परशुराम ने मानव जीवन को व्यवस्थित ढांचे में ढालने का महत्वपूर्ण कार्य किया। दक्षिण के क्षेत्र में जाकर वहां कमजोर समाज को एकत्रित कर समुद्र तटों को रहने योग्य बनाया। अगस्त ऋषि से समुद्र से पानी निकालने की विद्या सीख कर समुद्र के किनारों को रहने योग्य बनाया। एक बंदरगाह बनाने का भी प्रमाण परशुराम जी का मिलता है।

वही परशुराम जी ने कैलाश मानसरोवर पहुंचकर स्थानीय लोगों के सहयोग से पर्वत का सीना काटकर ब्रह्म कुंड से पानी की धारा को नीचे लाये जो ब्रह्मपुत्र नदी कहलायी। परशुराम जी को भगवान् विष्णु का आवेशावतार कहा जाना भी उचित नहीं है. वे आवेश, पराक्रम, अस्त्र शस्त्र के साथ ज्ञान, विवेक, बुद्धि व विज्ञान दृष्टि से भी संज्ञ, प्रज्ञ व विज्ञ थे। परशुराम जी ने समूची सामाजिक व्यवस्थाओं की स्थापना आर्यावर्त के कोने कोने में की थी. उस कालखंड में जब समाज में आर्य एक उपाधि या गुणसूचक विशेषण हुआ करता था, उन्होंने अनार्य, अघोरी, औघड़, अवर्ण, सवर्ण, सभी को आर्यश्रेष्ठ बनाने का ऋषिवत आचरण रखा था।

संविधान टकराव की नहीं, बल्कि संवाद, विचार–विमर्श और स्वस्थ बहस की अपेक्षा करता है: उपराष्ट्रपति

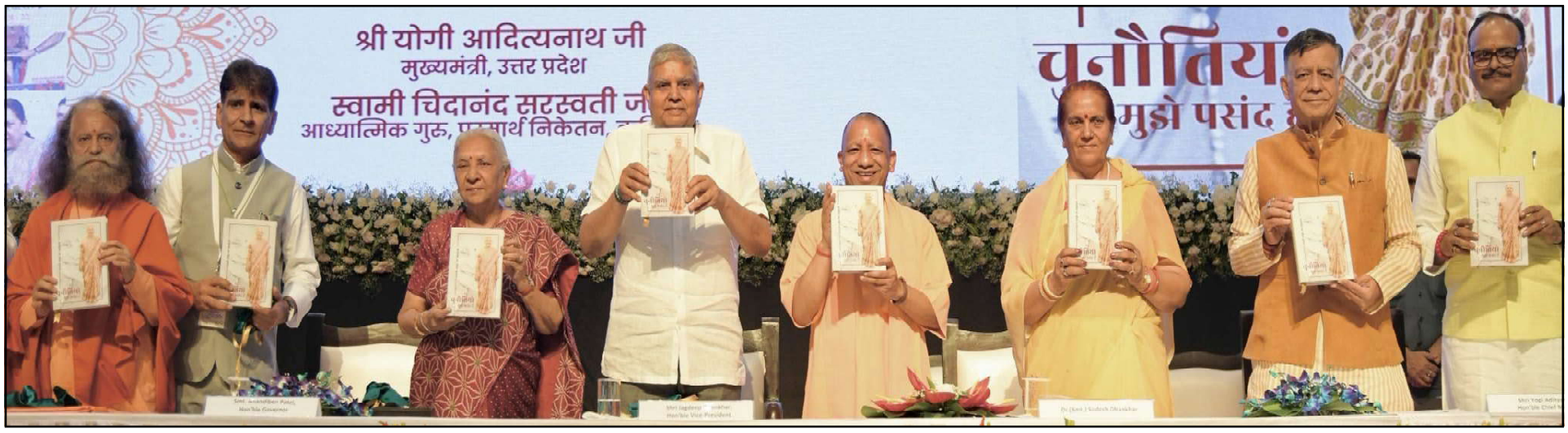

पीआईबी

नई दिल्ली। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने कहा कि मुझे चुनौतियाँ पसंद हैं और संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करना हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसमें कोई कोताही स्वीकार नहीं की जा सकती। "थोड़ी देर पहले मुझे कहा, आपको भी मुफ़्त में पुस्तक, नहीं मिलेगी। महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी, मुझे मुफ़्त में कोई भी चीज़ लेने की आदत नहीं है... सबसे खतरनाक चुनौती वह है, जो अपनों से मिलती है, जिसकी हम चर्चा नहीं कर सकते३..जो चुनौती अपनों से मिलती है, जिसका तार्किक आधार नहीं है, जिसका राष्ट्र विकास से संबंध नहीं है, जो राज–काज से जुड़ी हुई है। आप ही नहीं, मैं भी बहुत शिकार हूं, महामहिम राज्यपाल, इन चुनौतियों का मैं स्वयं शिकार हूं, भुक्तभोगी हूं। पर हमारे सामने एक बहुत बड़ी ताकत है और हमारी ताकत है हमारा दर्शन और जिन्होंने हमें कह रखा है, जब भी कोई संकट आए, वेद की तरफ ध्यान दो, गीता, रामायण, महाभारत की तरफ ध्यान दो "कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।" जब भी चुनौती सामने आए, चुनौतियां आएगी। चुनौतियां ऐसी आएंगी कि आप विवशता में पड़ जाते हो और सोचते हो, दीवारों के भी कान हैं। तो उस चुनौती की चर्चा खुद को भी नहीं करते हो पर कभी भी कर्तव्य पथ से अलग नहीं हटना है" उन्होंने आगे कहा।

लखनऊ में माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल की पुस्तक 'चुनौतियां मुझे पसंद है' के विमोचन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि, लोग कई बार कहते हैं कि जनता की याददाश्त कमज़ोर होती है और सोचते हैं कि समय के साथ सब बातें भुला दी जाएंगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्या हम इमरजेंसी को भूल गए हैं? बहुत समय बीत गया है, लेकिन इमरजेंसी की काली छाया आज भी हमें दिखाई देती है। यह भारतीय इतिहास का सबसे अंधकारमय काल था, जब लोगों को बिना कारण जेल में डाल दिया गया, न्यायपालिका तक पहुंच बाधित कर दी गई थी। मौलिक अधिकारों का नामोनिशान नहीं रहा, लाखों लोग जेलों में डाल दिए गए। हम इसे नहीं भूले हैं। उसी तरह हाल ही में जो पीड़ादायक घटना घटी है, मैं यह मानता हूं कृ और मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि हमें यह स्वीकार करना होगा कि हर व्यक्ति तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक वह अपराधी सिद्ध न हो जाए। लोकतंत्र में निर्दोषता की एक विशेष महत्ता होती है। लेकिन कोई भी अपराध हो, उसका समाधान कानून के अनुसार ही होना चाहिए। और यदि कोई अपराध आम जनमानस को झकझोरता है, तो उस पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। मैंने इस बात को पूरी स्पष्टता से कहा है। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि आप इस विषय पर इतने बेबाक क्यों हैं? मुझे बहुत प्रेरणा मिली महामहिम राज्यपाल की पुस्तक से। और मैंने यह स्पष्ट किया है कि मुझे चुनौतियाँ पसंद हैं और संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करना हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसमें कोई कोताही स्वीकार नहीं की जा सकती।

संवैधानिक पदों पर हुई टिप्पणियों के प्रति गहरी चिंता ज़ाहिर करते हुए श्री धनखड़ ने कहा, हमारे संविधान में दो पद सर्वोच्च माने गए हैं एक है भारत के राष्ट्रपति का, और दूसरा राज्यपाल का। और माननीय मुख्यमंत्री जी, वे इसलिए सर्वोच्च हैं क्योंकि जो शपथ आपने ली है, जो शपथ मैंने ली है, जो शपथ सांसद, मंत्री, विधायक या किसी भी न्यायाधीश ने ली है वह शपथ होती हैरू मैं संविधान का पालन करूँगा। लेकिन द्रौपदी मुर्मू जी (राष्ट्रपति) और आनंदीबेन पटेल जी (राज्यपाल) की शपथ इससे अलग है। उनकी शपथ होती हैरू मैं संविधान की रक्षा करूँगा, उसका संरक्षण और बचाव करूँगा। और दूसरी शपथ होती है मैं जनता की सेवा करूंगा। राष्ट्रपति के लिए भारत की जनता की और राज्यपाल के लिए संबंधित राज्य की जनता की। ऐसे गरिमापूर्ण और संवैधानिक पदों पर यदि टिप्पणियाँ की जाती हैं, तो वह मेरे अनुसार चिंतन और मनन का विषय है।

संविधान द्वारा निर्मित सभी संस्थाओं के बीच समन्वय और संवाद के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उपराष्ट्रपति ने रेखांकित किया, " हाल के कुछ दिनों में एक घटनाक्रम हुआ है, जिस पर मैंने वक्तव्य भी दिया है और वह आपके प्रांत से भी जुड़ा हुआ है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि इसी प्रांत में विधायिका और न्यायपालिका के बीच सबसे बड़ा टकराव हुआ था। आप सभी इस विषय से भली भांति परिचित हैं। हमारा यह परम कर्तव्य है कि हम सुनिश्चित करें कि हमारी संवैधानिक संस्थाएं एक–दूसरे का सम्मान करें, और यह सम्मान तब और बढ़ता है जब हर संस्था अपनी सीमाओं के भीतर रहकर कार्य करती है। जब संस्थाएं एक–दूसरे का सम्मान करती हैं हमारा संविधान टकराव की नहीं, बल्कि समन्वय, सहयोग, संवाद, विचार–विमर्श और स्वस्थ बहस की अपेक्षा करता है। संविधान संस्थाओं के बीच संघर्ष की कल्पना नहीं करता, वह सहभागिता और संतुलन की भावना को बढ़ावा देता है।

इसी संदर्भ में उन्होंने आगे कहा, सभी संस्थाओं की अपनी–अपनी भूमिका होती है। किसी एक को दूसरे की भूमिका नहीं निभानी चाहिए। हमें संविधान का सम्मान करना चाहिए अक्षरशः, भावना में और सार में भी। और मैं पहले भी कह चुका हूँ, 140 करोड़ जनता अपनी भावना चुनाव के माध्यम से व्यक्त करती है, अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, और वही जनप्रतिनिधि जनता के मानस को प्रतिबिंबित करते हैं, और जनता उन्हें चुनावों में जवाबदेह भी बनाती है। और इसलिए मैंने आम आदमी की भाषा में कहा है कि जैसे विधायिका कोई फैसला नहीं लिख सकती, वह न्यायालय का कार्य है उसी तरह न्यायालय कानून नहीं बना सकता। मुझे न्यायपालिका के प्रति अत्यंत सम्मान है, मैं न्यायपालिका का एक सिपाही रहा हूँ। मैंने चार दशक से भी अधिक समय वकील के रूप में बिताया है। केवल 2019 में, जब मुझे पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया, तब मैंने वकालत छोड़ी। मैं जानता हूँ कि न्यायपालिका में अत्यंत प्रतिभाशाली लोग हैं। न्यायपालिका का बहुत बड़ा महत्व है। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था कितनी मजबूत है यह न्यायपालिका की स्थिति से परिभाषित होती है। वैश्विक मानकों पर हमारे न्यायाधीश सर्वश्रेष्ठ में से हैं। लेकिन मैं अपील करता हूँ कि हमें सहयोग, समन्वय और सहभागिता की भावना दिखानी चाहिए। कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका इन संस्थाओं को एकजुट होकर और आपसी तालमेल से काम करना चाहिए। प्रजातंत्र में अभिव्यक्ति और वाद–विवाद के महत्व पर ज़ोर देते हुए श्री धनखड़ ने कहा, "एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है, जो हम सभी के लिए अत्यंत आवश्यक है। हम अपने आपको प्रजातंत्र क्यों कहते हैं? आर्थिक उन्नति, संस्थागत ढांचे का विकास, तकनीक का विस्तार ये सब महत्वपूर्ण हैं। लेकिन प्रजातंत्र की असली परिभाषा है अभिव्यक्ति और वाद–विवाद। अभिव्यक्ति और संवाद ही लोकतंत्र का आधार हैं। यदि अभिव्यक्ति पर अंकुश लगने लगे, तो किसी भी राष्ट्र के लिए अपने आप को लोकतांत्रिक कहना कठिन हो जाएगा। लेकिन अभिव्यक्ति का कोई अर्थ नहीं रह जाता यदि उसके साथ वाद–विवाद न हो। यदि अभिव्यक्ति इस हद तक पहुँच जाए कि बोलने वाला यह समझे कि ष्मैं ही सही हूँ और बाकी सभी परिस्थितियों में गलत हैं, उनकी बात सुनने का कोई प्रयास ही न हो तो यह अभिव्यक्ति का अधिकार नहीं, बल्कि उसका विकार बन जाता है। लोकतंत्र तभी परिभाषित होता है जब एक समग्र पारिस्थितिकी तंत्र में अभिव्यक्ति और संवाद एक साथ फलते–फूलते हैं। ये दोनों एक–दूसरे के पूरक हैं। और यदि अभिव्यक्ति चरम पर पहुँच जाए लेकिन संवाद न हो, तो हमारे वेदों का जो दर्शन है अनंतवाद, वह समाप्त हो जाएगा। और उसके स्थान पर जन्म होगा अहम और अहंकार का। यह अहम और अहंकार व्यक्ति और संस्था दोनों के लिए घातक हैं।

इस कार्यक्रम के अवसर पर उपराष्ट्रपति की धर्मपत्नी श्रीमती सुदेश धनखड़, उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना एवं अन्य गणमान्य अतिथि मौजूद रहे।

मतदाता सूचना पर्चियों को और अधिक मतदाता अनुकूल बनाया जाएगा

पीआईबी

नई दिल्ली। भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची की सटीकता में सुधार और नागरिकों के लिए मतदान प्रक्रिया को और अधिक सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से नई पहल की है। ये उपाय इस वर्ष मार्च में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) श्री ज्ञानेश कुमार ने निर्वाचन आयुक्तों डॉ सुखबीर सिंह संधू और डॉ विवेक जोशी की उपस्थिति में मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) के सम्मेलन के दौरान परिकल्पित पहलों के अनुरूप हैं। आयोग अब मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के नियम 9 और जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 (वर्ष 2023 में संशोधित) की धारा 3(5)(बी) के अनुरूप भारत के महापंजीयक से इलेक्ट्रॉनिक रूप से मृत्यु पंजीकरण डेटा प्राप्त करेगा।

इससे निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ) को पंजीकृत मृत्यु के बारे में समय पर जानकारी प्राप्त हो सकेगी। इससे बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) को फॉर्म 7 के अंतर्गत औपचारिक अनुरोध की प्रतीक्षा किए बिना, क्षेत्रीय दौरों के माध्यम से सूचना का पुनः सत्यापन करने में सहायता मिलेगी। मतदाता सूचना पर्चियों (वीआईएस) को मतदाताओं के लिए अधिक अनुकूल बनाने के लिए आयोग ने इसके डिजाइन में भी परिवर्तन करने का निर्णय किया है।

मतदाता का सूची क्रमांक और भाग संख्या अब अधिक प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी, साथ ही फॉन्ट का आकार भी बढ़ाया जाएगा, जिससे मतदाताओं के लिए अपने मतदान केंद्र की पहचान करना और मतदान अधिकारियों के लिए मतदाता सूची में उनके नाम को सुगमतापूर्वक ढूंढना आसान हो जाएगा।

आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि सभी बीएलओ, जिन्हें जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13बी (2) के अंगर्गत ईआरओ द्वारा नियुक्त किया जाता है, को मानक फोटो पहचान पत्र जारी किए जाएं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मतदाता सत्यापन और पंजीकरण अभियान के दौरान नागरिक बीएलओ को पहचान सकें और उनके साथ आत्मविश्वास से बातचीत कर सकें। चुनाव संबंधी कर्तव्यों के निष्पादन में मतदाताओं और भारत निर्वाचन आयोग के बीच पहले इंटरफेस के रूप में, यह महत्वपूर्ण है कि घर–घर जाकर दौरा करते समय बीएलओ जनता के लिए आसानी से पहचाने जा सकें।

कांग्रेस ने किया संविधान का सर्वाधिक दुरूपयोगः मथुरा दत्त जोशी

शत्रुघ्न संवाददाता

हरिद्वार। वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व दर्जा राज्य मंत्री मथुरा दत्त जोशी ने कांग्रेस द्वारा आयोजित संविधान बचाओ रैली को राजनीतिक नौटंकी बताते हुए कहा कि कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में एकजुटता से आगे बढ़ रहा है। लेकिन अपने नकारात्मक रुख के चलते, कांग्रेस और उनकी सहयोगी पार्टियों को अपना राजनैतिक भविष्य शून्य की तरफ खिसकता नजर आ रहा है। यही वजह है कि वे हताशा निराशा में लगातार देश में भ्रम और झूठ फैलाने की राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रैस क्लब में आयोजित पत्रकारवार्ता को संबोधित करते हुए मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की प्रस्तावित संविधान बचाओ रैली भी देश और समाज को बरगलाकर, अराजक माहौल पैदा कर जनता के आत्मविश्वास को कमजोर करने की योजना का हिस्सा है।

जोशी ने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी प्रत्येक पार्टी को अपनी बात रखने का अवसर देती है। लेकिन बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है कि यह सब उस समय किया जा रहा है। जब देश पहलगामा हमले से दुख और आक्रोश में है और पीएम मोदी के नेतृत्व में दुश्मनों को करारा जवाब देने की तैयारी में जुटा हुआ है। उन्होंने कहा कि देश में आपातकाल लगाने की जिम्मेदार कांग्रेस संविधान बचाने का दावा कर रही है। जबकि संविधान का सबसे अधिक दुरूपयोग कांग्रेस ने ही किया है। हाईकोर्ट के एक फैसले से खुद का सिंहासन हिलते देख तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश के लोकतंत्र को बंधक बनाकर आपातकाल थोप दिया था। संसद, न्यायपालिका, कार्यपालिका और पत्रकारिकता सभी का दमन करने का प्रयास किया। कांग्रेस ने धारा 356 का भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। कांग्रेस और उसके सहयोग से चली सरकारों ने 102 बार धारा 356 का दुरूपयोग कर निर्वाचित सरकारों को अस्थिर किया।

इतना ही संविधान की मूल प्रस्तावना से छेड़छाड़ करते हुए उसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्दों को जोड़ा गया। संविधान के विपरीत जाकर जम्मू–कश्मीर में धारा 370 लागू कर उसे देश से अलग दिखाने का पाप किया। एक देश में दो संविधान, दो विधान और दो निशान की भावना ने कश्मीर को आतंक की भट्टी में झोंके रखा। भाजपा ने बहुमत का उपयोग मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक के श्राप और वक्फ बोर्ड की माफियागिरी से आजाद करने के लिए किया। लेकिन कांग्रेस ने राजीव गांधी को मिले दो तिहाई बहुमत का दुरूपयोग पीड़ित बुजुर्ग महिला शाहबानों के साथ अन्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदलने में किया। प्रैसवार्ता में मुख्य रूप से पूर्व जिला अध्यक्ष संदीप गोयल, महामंत्री आशु चौधरी, जिला उपाध्यक्ष लव शर्मा एवं जिला मीडिया प्रभारी नितिन चौहान, युवा नेता सूर्यकांत सैनी मौजूद रहे।

निष्पक्ष पत्रकारिता भी संकट के दौर से गुजर रही हैः राजेंद्र चौधरी

संवाद कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे सपा नेता राजेंद्र चौधरी का प्रेस क्लब अध्यक्ष धर्मेन्द्र चौधरी व महामंत्री दीपक मिश्रा ने किया स्वागत

शत्रुघ्न संवाददाता

हरिद्वार। प्रेस क्लब द्वारा आयोजित संवाद कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी का प्रेस क्लब अध्यक्ष धर्मेंद्र चौधरी एवं महामंत्री दीपक मिश्रा ने स्वागत कर स्मृति चिन्ह भेंट किया। प्रेस क्लब में पत्रकारों से बातचीत के दौरान राजेंद्र चौधरी ने कहा कि निष्ठा ईमानदारी से निष्पक्ष पत्रकारिता करना भी संकट के दौर से गुजर रहा है। लोकतंत्र में पत्रकारिता को जीवित रखने का दायित्व पत्रकार समाज पर है।

उन्होंने पत्रकारों पर हो रहे हमले की कठोर शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि अनियंत्रित होती नौकरशाही के कारण नैतिक मूल्य तहस–नस हो रहे हैं। राजेंद्र चौधरी ने कहा कि भ्रमजाल फैलाया जा रहा है। सत्य को असत्य करने की कोशिश की जा रही है। समाज में दूरियां बढ़ रही है। भाईचारा समाप्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा खतरा नफरत का बाजार है। नौजवान, किसान हताशा निराशा का सामना कर रहे हैं। नौजवान रोजगार के लिए परेशान है। महिलाओं का जीवन भी संकट में है। महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी मानती है कि सामाजिक न्याय सबसे बड़ा माध्यम होना चाहिए। पिछड़ों और वंचितों को अवसरों से दूर रखा जा रहा है। राजनीति भी ईमानदारी से की जा सकती है। लोकतंत्र में हालात बदले बदले से हैं। चारों तरफ अराजकता फैली हुई है। कानून को मनमाने तरीके से चलाया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री कार्यकाल में उत्तर प्रदेश का चहुंमुखी विकास हुआ। सभी वर्गों के हितों में काम किए गए। बढ़ती महंगाई के कारण आम लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है। किसान मजदूर परेशान है। लेकिन भारत की जनता के पास सबसे बड़ी ताकत है। राजनीति में संविधान एवं जनता सर्वपरी है। सत्ता में बैठी सरकार को जनता के हितों में फैसले लेने चाहिए। लोकतंत्र के मूल्यों को समझने की आवश्यकता है। इस दौरान सपा नेता महंत शुभम गिरी ने राजेंद्र चौधरी, प्रो.बी.पांडेय को चित्र प्रदान किया। सपा शिक्षक सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनेंद्र मिश्र, उत्तराखंड के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष डा.राजेंद्र पाराशर मशकुर कुरैशी, महेन्द्र यादव, पूर्व महानगर अध्यक्ष लव कुमार दत्ता, पूर्व प्रदेश महासचिव महंत शुभम गिरी, नरेन्द्र गुर्जर, जयराम सैनी, नैन सिंह, सपा छात्र सभा पूर्व महानगर अध्यक्ष कपिल शर्मा जौनसार आदि सपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। प्रेस क्लब के सुनील पाल, राहुल वर्मा, अमित शर्मा, रोहित सिखौला, दीपक नौटियाल, सुनील दत्त पांडेय, ललितेंद्रनाथ, आशीष मिश्रा, नरेश गुप्ता, मयूर सैनी ने राजेंद्र चौधरी का स्वागत किया।

स्वामी श्रीमती दुर्गेशनन्दिनी फरलिया, मुद्रक, प्रकाशक, सम्पादक बालकृष्ण शर्मा द्वारा अमर प्रिन्टिंग प्रेस, मौ. कड़च्छ, ज्वालापुर, हरिद्वार से मुद्रित करवाकर बी–72 न्यू विष्णु गार्डन, पो.गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार, उत्तराखण्ड से प्रकाशित।
आर.एन.आई.संख्या–23316/72
प्रधान सम्पादक
श्रीमती दुर्गेशनन्दिनी फरलिया
सम्पादक
बालकृष्ण शर्मा
कानूनी सलाहकार
राजेन्द्रनाथ गोस्वामी
एडवोकेट

नोट–समस्त विवाद हरिद्वार न्यायालय के अधीन मान्य होंगे।